

सं. ओ.वि./23033.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. खरैती राम मल्होत्रा कन्सीट्यूटड अथोरटी कम जनरल मैनेजर, हुन्डे वाला फार्म, जगाधरी, के श्रमिक श्री राम पाला तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3-(44)84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम पाला की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस सहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./23039.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. खरैती राम मल्होत्रा कन्सीट्यूटड अथोरटी कम जनरल मैनेजर हुन्डे वाला फार्म जगाधरी, के श्रमिक श्री राम चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3-(44)84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम चन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

जे. पी. रतन,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

श्रम विभाग

दिनांक 29 मई, 1985

सं. ओ.वि./एफ.डी./6-84/23020.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. डायरेक्टर/प्रिन्सीपल वाई०एम० सी०ए० इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग, फरीदाबाद, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है/हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है/हैं न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या सस्था के नान-टीचिंग कर्मचारी तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल, 1976 से वेतन रिवीजन के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण में?

कुलवंत सिंह,

वितायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।